



- वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमरीकी सैन्य कार्रवाई की दुनियाभर में कड़ी निन्दा की गई।
- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा तीन नए अपराधिक कानूनों से दोषसिद्धि दर बढ़ेगी और जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी।
- चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।
- चवालीस दिवसीय माघ मेले का पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुभारंभ हुआ। प्रयागराज में पहले दिन इक्कीस लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया।



वेनेजुएला में अमरीका के हमलों की खबर के बीच राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। राजधानी काराकस में सात विस्फोटों और कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों की आवाजें सुनने के बाद वेनेजुएला सरकार ने अमरीका पर कई राज्यों में नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले का आरोप लगाया है। इस बीच, काराकस में विस्फोटों से पहले जारी सैन्य गतिविधि के मद्देनजर संघीय विमानन प्राधिकरण ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में अमरीकी वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वेनेजुएला में अमरीका की सैन्य कार्रवाई को एक खतरनाक मिसाल करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने एक बयान में कहा कि महासचिव एंतोनियो गुतेरस इस बात से बेहद चिंतित हैं कि इस अभियान के गंभीर क्षेत्रीय परिणाम हो सकते हैं। अमरीका की सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद विश्व नेताओं की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं। रूस, चीन, ईरान, ब्राजील और क्यूबा सहित कई देशों ने अमरीका की सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे वेनेजुएला की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है। वेनेजुएला ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाली अमरीका की सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इस कार्रवाई को गंभीर सैन्य आक्रामकता करार दिया है। देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर राष्ट्रपति मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की है।



उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के जीवित होने का प्रमाण मांगते हुए उनके ठिकाने का खुलासा करने की मांग की है। रक्षामंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज़ ने देशभर में सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा की है। वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने इसे वेनेजुएला के खिलाफ अमरीका की सैन्य आक्रामकता बताते हुए इसकी निंदा की है। चीन ने भी अमरीका के हवाई हमलों की निंदा करते हुए इन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन ठहराते हुए इन्हें वर्चस्ववादी कार्रवाई बताया। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल ने भी हमले की निंदा करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल प्रतिक्रिया की मांग की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को आक्रामकता बताया और संयुक्त राष्ट्रचार्टर तथा संप्रभु देश के खिलाफ बल के प्रयोग को प्रतिबंधित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमरीकी हमलों और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इस बीच यूरोपीय नेताओं ने संयम बरतने का आग्रह किया।



यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि किसी भी समाधानमें अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान होना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि उनका देश इस अभियान में शामिल नहीं है और उन्होंने अमरीकी समकक्षों के साथ बातचीत जारी रखते हुए अंतरराष्ट्रीय कानूनका पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने तनाव कम करने का आह्वान किया जबकिफ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ ने कहा कि फ्रांस वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहालीका समर्थन करता है।



गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीन नए आपराधिक कानून वर्ष दो हजार उनतीस तक सत्र न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कल द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि इन कानूनों से जांच में तेजी आ रही है और दोषसिद्धि दर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने दो हजार उन्नीस से संसदीय परामर्श समिति की बारह बैठक की हैं, जिनके परिणाम सकारात्मक मिले हैं। श्री शाह ने कहा कि दो हजार इक्कीस में देश में एक भी मोबाइल फोरेंसिक लैब नहीं थी, जबकि आज इनकी संख्या एक हजार तक पहुंच गई है। देश में फोरेंसिक लैब का नेटवर्क अगले पांच

वर्ष में स्थापित करने के लिए तीस हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। वर्ष दो हजार उनतीस तक देश के प्रत्येक राज्य में एक फोरेंसिक विश्वविद्यालय या एक केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला होगी।



चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, 2 से 4 जनवरी तक द्वीप समूह के आधिकारिक दौरे पर हैं। यह दौरा देश की सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस द्वीप श्रृंखला में रक्षा और विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के उद्देश्य से किया जा रहा है। दौरे के दौरान कल जनरल अनिल चौहान ने श्री विजयपुरम स्थित लोक निवास में द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी. के. जोशी से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में द्वीप समूह के समग्र विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान दोहरे उपयोग वाले रणनीतिक बुनियादी ढांचे (सैन्य एवं नागरिक दोनों के लिए उपयोगी), नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास, मौजूदा रनवे के उन्नयन और उनकी लंबाई बढ़ाने, गहरे पानी के बंदरगाहों के निर्माण, तथा भविष्य की विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही, क्षेत्र की तटीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के उपायों पर भी गहन चर्चा हुई। यह बैठक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सामरिक भूमिका को सुदृढ़ करने, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के समन्वित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस दौरे से क्षेत्र में रक्षा तैयारियों को मजबूती मिलने के साथ-साथ स्थानीय विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।



पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ चवालीस दिन चलने वाले माघ मेले की शुरुआत कल तड़के में प्रयागराज के संगम पर हुई। माघ मेला प्राधिकरण के अनुसार इक्कीस लाख पचास हजार श्रद्धालुओं ने कल शाम चार बजे तक संगम में पवित्र स्नान किया। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इस बार मेला क्षेत्र आठ सौ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को सात खंडों में विभाजित किया गया है। लगभग चार सौ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट मनीष वर्मा ने कहा कि अधिकारी लगातार चौकसी बरत रहे हैं। माघ मेले के दौरान छह प्रमुख स्नान अवसर होंगे। इसका समापन महाशिवरात्री पर पवित्र स्नान के साथ होगा।



प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच, प्रगति ने पचासवीं बैठक के सफल आयोजन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति की शुरुआत की थी। प्रगति ने प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के माध्यम से प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में क्रांति पैदा की है। यह मंच सहकारी संघवाद का एक आदर्श उदाहरण है। इसमें केंद्र, राज्य और केंद्रीय मंत्रालय एक ही डिजिटल इंटरफेस पर मौजूद हैं। एक दशक से अधिक समय में, प्रगति ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान करने और उत्तरदायित्व की एक मजबूत संस्कृति को प्रोत्साहन देने में सहायता की है। यह निगरानी के साथ शासन सुधारों का मंच बन गया है।

